# ‘बैठक’ में ‘भाग’ लीजिए, ‘पांच’ लाख ले ‘जाइए’

## फिर ब्लैक मेल के शिकार हुए ‘संजय’, कब तक होते रहे शिकार, 18-20 करोड़ की खरीदी गई जमीन की जांच करवाने की दी गई धमकी

▸▸ रामजी का शपथ ले कर न बिकने की कसम खाने वाले आखिर फिर बिक ही गए ▸▸ कुर्सी को लात मारने और न झुकने की कसमें खाने वाले अध्यक्ष को सदस्यों के सामने क्यों झुकना ही पड़ा ▸▸ कोरम पूरा करने की कीमत दो करोड़ 45 लाख चुकानी पड़ी, अध्यक्ष ने कहा कि पैसा तो दे रहा हूं मगर, सभी 26 सदस्य आने चाहिए, नहीं आएगें तो पैसा वापस करना पड़ेगा ▸▸ सदस्यों की अगुवाई करने वाले ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए चली दूसरी बार चाल ▸▸ अध्यक्ष और 42 सदस्य इस बात की बैठक नहीं करते कि कैसे जिला पंचायत से भ्रष्टाचार समाप्त हो, और जिले में गुणवत्तापरक कार्य, इनकी बैठके ब्लैक मेल के जरिए धन एठने की होती

तेजयुग न्यूज

**बस्ती :** बस्ती का जिला पंचायत प्रदेश/देश का पहला ऐसा पंचायत होगा, जहां पर अध्यक्ष से लेकर अधिकांश जिला पंचायत सदस्य, कैसे जिले का विकास हो, गुणवत्तापरक कार्य हो और कैसे इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, को लेकर गुप्त बैठकें नहीं होती, बल्कि इस लिए होती है, ताकि अध्यक्ष को ब्लैक मेल के जरिए कितने धन की वसूली की जाए। इन बैठकों की अगुवाई करने वाले का जब अपना मकसद पूरा हो जाता है, तो यह उस जिला पंचायत सदस्यों के हितों के लिए बनाए गएं संघ की भी तिलांजलि दे देते है।

सदस्य भी अगुवाई करने वाले के झांसे में बार-बार आ जाते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हो जाते है। कभी जिला पंचायत अध्यक्ष की लाइन में रहे, का तो अपना मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन जिनके कंधें में रखकर बंदूक चलाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आता। बार-बार सवाल उठ रहा है, कि वह अध्यक्ष जो खुले आम यह कहता हो कि न तो वह झुकेगें और न ही टूटेंगे, इस तरह की दस कुर्सी को लात मार दूंगा, मगर मान और सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करुंगा, अगर वही अध्यक्ष बयान देने के तीन-चार दिन भी नहीं बीता हो, और जाकर सदस्यों के सामने झुक जाए तो जनता इसे क्या माने, किसे चालाक समझे और किसे बेवकूफ? अगर अध्यक्ष को बैठक का कोरम पूरा करने के लिए ब्लैक मेल होना पड़े तो अध्यक्ष और जिला पंचायत का भगवान ही मालिक। दुनिया की यह पहली ऐसी बैठक होगी, जिसका कोरम पूरा करने के लिए दो करोड़ 45 लाख की कुर्बानी देने की योजना बनी।

पहली बार सदस्यों की कीमत पांच लाख तक पहुंची, वरना इनकी कीमत कौन नहीं जानता। यह भी सही है, कि दो मार्च 24 के बाद सदस्यों की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसका खुलासा मीडिया कर भी चुकी है, और यह सब कुछ एकता का नतीजा रहा। अगर यही एकता आगे भी रही है, तो अधिकांष सदस्यों की कीमत कार्यकाल समाप्त होते-होते दस लाख तक पहुंच सकती है। मगर, यह सब कुछ सदस्यों की एकता पर निर्भर रहेगा। इन्हें अच्छी कीमत भी मिलेगी और क्षेत्र में इन्हें बराबर का काम भी मिलेगा। अनेक सदस्यों ने कहा भी इस बार फुल प्रूफ तैयारी रही, अध्यक्ष को झुकाने के लिए इनके उन जमीनों को भी खंगाला गया, जो इन्होंने हाल ही में 18-20 करोड़ की लागत से खरीदी है। सदस्यों के बात में कितना दम है, यह तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, मगर, थोड़ी बहुत सच्चाई का पता इस बात से चलता है, कि जो अध्यक्ष, सांसद के सामने नहीं झुका वह अचानक अगुवाई करने वाले और सदस्यों के सामने कैसे झुक गया? यह भी सही है, कि अगर अध्यक्ष न झुकते तो सदस्यों की कीमत पांच लाख तक नहीं पहुंची।

**तेजयुग फॉलोअप खबर**

अंदरखाने की खबर है, कि जिन शर्तो पर अध्यक्ष झुकने को तैयार हुए, उनमें एक षर्त यह भी है, कि सभी 26 सदस्यों को 12 मार्च की बैठक में आना ही होगा। यह भी कहा गया कि अगर सदस्य नहीं आए तो पैसा वापस करना पड़ेगा। इसकी गांरटी देने को कहा गया, इस पर कहा गया कि अगर दस-बीस हजार वापस करने की गांरटी देनी पड़ती तो उसे दिया जा सकता है, लेकिन लाखों की गांरटी कौन देगा? इससे पता चलता है, अगुवाई करने वाले को खुद अपने साथियों पर भरोसा नहीं है। यह भी कहा गया कि जो पैसा दिया जा रहा है, वह न तो गेहूं और न जमीन बेचकर दिया जा रहा है, अगर ऐसे हराम के पैसों को सदस्यों ने हड़प भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पैसा पहले नहीं दिया जाएगा, नही ंतो न जाने कौन पैसा लेकर फरार हो जाए और बैठक में न आए, इस लिए यह पैसा तब दिया जाएगा, जब सदस्य बैठक में भाग लेकर वापस आएगे। चूंकि पैसे के मामले में सदस्यों का अध्यक्ष पर से विष्वास उठ चुका है, इस लिए यह कहा गया, जब पैसा एडवांस में मिल जाएगा तो बैठक में भाग लेंगे, इस बात पर भी सहमति बनी कि पैसा किसके पास रहेगा। ताकि कोई धोखा न हो। तय हुआ कि पैसा अगुवाई करने वाले के पास रहेगा। तब जाकर 12 मार्च 24 को बैठक की तिथि निष्चित हुई। अगर, कहीं इंकम टैक्स का छापा अगुवाई करने वाले के आवास/कार्यालय में पड़ गया तो, हिसाब देते नहीं बनेगा। यह उन असली/नकली जिला पंचायत सदस्यों का सच है, जो सांसदजी के आगे-पीछे हमेषा घूमते रहते है। क्या ऐसे लोगों से सांसदजी को यह उम्मीद होगी कि यह लोग चुनाव में हजार-पांच सौ वोट दिला पाएगें?

जब दो मार्च की बैठक का बहिष्कार करने वालों से 12 मार्च के बैठक के बाद मीडिया सवाल करेगी कि कैसे और किन शर्तो पर आप लोग तैयार हो गए, तब शायद इन लोगों को मुंह छिपाने के आलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तब न यह न अध्यक्ष को भ्रष्टाचारी कह पाएगें और न आरोप ही लगा पाएगें। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है, कि जिन 26 सदस्यों ने रामजी की फोटो को हाथ में लेकर यह कसम खाया था, और जिसका वीडियो भी बनाया कि, अब वह लोग न तो बिकेगें और न अध्यक्ष के साथ जाकर फोटो ही खिचवाएगें, यह भी कहा गया कि अगर किसी ने बिकने की कोशिश की तो उसी दिन उस सदस्य का वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब देखना है, कि 12 मार्च को वीडियो वायरल होता है, कि नहीं? यह भी सही है, कि अगर लेन-देन का सौदा तय नहीं हुआ तो बैठक 12 मार्च को नहीं रखी जाती। कहने का मतलब जो लोग अभी तक यह कह रहे थे, वह नहीं बिकेगें, उनका भी ईमान पांच लाख में डगमगा गया, और अब कह रहे हैं, कि मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे? इस बार अध्यक्ष की जीत नहीं मानेगी, बल्कि उनकी दूसरी बार हार मानी जाएगी, क्यों कि जिस कीमत पर जीत मिलेगी, वह उन्होंने मेहनत से नहीं कमाया, और न इस बार होटल ही गिरवी रखा।

# ‘पत्रकारजी’ पिछवाड़े में ‘दम’ हो तो बिना ‘बखरा’ के फाइल पास ‘कराइए’

## कमिश्नर, डीएम, सीडीओ और डीसी मनरेगा देख लीजिए अपने बीडीओ का सच

तेजयुग न्यूज

**बस्ती।**...प्रधान और ब्लॉक का नाम इस लिए नहीं बताया जा रहा है, ताकि प्रधान की बीडीओ साहब रोजी रोटी न बंद कर दे। प्रधान यह जानते हुए कि वह यह बात किससे और किसके बारे में कह रहा है, फिर भी उसने अपना दर्द और मनरेगा को लूटने वालों के बारे में खुलकर बताया। कहा कि पत्रकार साहब अगर पिछवाड़े में इतना दम हो तो यह फाइल है, बिना बखरा के स्वीकृति करवा दीजिए, तब मानूंगा कि आप पत्रकार हैं। दावे के साथ यह भी कहा कि जिस फाइल को आप बिना बखरे के स्वीकृति कराएगें, उस कार्य पर वहीं मजदूर काम करेगें और हाजीरी लगेगा, जिनका मस्टरोल निकला है। कहा कि अभी-अभी तीन लाख बखरा देकर आया हूं, तब यह दस लाख की फाइल स्वीकृति हुई है। 30 लाख की तीन फाइल दिखाते हुए कहा कि जब उसके पास दस लाख हो जाएगा तो वह बीडीओ साहब के पास जाएगें। इसी तीनो फाइल को प्रधान पत्रकारों को चैलेंज कर रहा है, कि बिना बखरा के स्वीकृति कराइए तब मानूगां कि आप लोग असली पत्रकार है।

**❖ कहा कि पत्रकारजी वादा करता हूं कि अगर बिना बखरा के फाइल आपने स्वीकृति करा दिया, फर्जी मस्टरोल नहीं भरुगां**
**❖ नाहक ही आप लोग प्रधानों को परेशान करते हैं, साढ़े नौ लाख चुनाव में खर्च किया, अभी वसूल नहीं पाया**
**❖ जाइए उन बीडीओ को परेषान करिए जो दो लाख वेतन पाते हैं, और बिना बखरा लिए फाइल छूते नहीं**
**❖ बीडीओ से बढ़कर तो प्रमुखजी है, जो बीडीसी से 40 फीसद बखरा लेते, इसी लिए कोई काम ही करता और फर्जी भुगतान लेता**

बताया कि बीडीओ साहब खुले आम एडवांस में चार और तीन फीसद बखरा इस लिए लेते हैं, कि अगर कहीं तबादला हो गया तो कम से कम बखरा तो न डूबे। इस प्रधान ने नकली प्रमुख का पोल भी खोला और कहा कि 40 फीसद बखरा बीडीसी से लेते हैं, चाहें काम हो या न हो। पत्रकारों से प्रधान यह भी कह रहा है, कि नाहक आप लोग प्रधान को परेशान करते हैं, पत्रकार से कहा भी प्रधान बनकर दिखाइए तब पता चला कि एक प्रधान किन-किन परिस्थितियों से गुजरता है। सवाल करते हैं, कि जिस काम के लिए प्रधान को 28 फीसद बखरा देना पड़े, क्या उस कार्य को ईमानदारी से किया जा सकता है? कहते हैं, कि आप लोग जो रोज फर्जी मस्टरोल और फर्जी मजदूरों की हाजीरी लगाने वाली खबर लिखते हो, इससे उनका और नुकसान होता, अधिकारी आप की खबर पर कार्रवाई करने के बजाए मामले को रफा-दफा करने के लिए दोहन करता है। तब यह बखरा बढ़कर 50 फीसद से उपर चला जाता हैं। इस लिए अगर आप लोग वाकई भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, तो प्रधान के बजाए असली/नकली प्रमुख, सचिव और बीडीओ पर मिलकर हमला बोलिए। वाकई अगर कुछ भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं, तो प्रधानों के खिलाफ लिखने के बजाए प्रमुख और बीडीओ के खिलाफ लिखिए। तब प्रधान भी आप का साथ देगा। यह भी कहते हुए नहीं चूकते कि प्रधान तो आप लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और आप लोग हम्हीं लोगों को ही परेशान करते है।

प्रधान ने यहां तक कहा कि वह ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और गांव वालों की नजर में चोर नहीं बनना चाहते, मगर बीडीओ और सचिव, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक नहीं करने देतें, अगर अधिक ईमानदार बनने का प्रयास करुंगा तो चुनाव का खर्चा निकालने को कौन कहे भूखे रहने की नौवत आ जाएगी। कहा कि उनके ब्लॉक में जिन प्रधानों ने ईमानदारी दिखाने का प्रयास किया, उसे बीडीओ कौन कहे, ब्लॉक का चपरासी तक बात करना नहीं चाहते, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ब्लॉक पर जहां कुर्सी और चाय-पानी मिलना चाहिए, वहां उसे दुत्कार मिलता है। उन्हीं प्रधानों का आवभगत होता है, जो बीडीओ और सचिव के मानक पर खरा उतरतें है। प्रधान ने कमिष्नर, डीएम, सीडीओ और डीसी मनरेगा से अपील के लहजे में कहा कि आप लोग अपने बीडीओ को सुधार लीजिए, मनरेगा सुधर जाएगा। यह एक प्रधान का दर्द नहीं हैं, इनके जैसे न जाने कितने प्रधान होगें, जो चोरी तो बीडीओ, सचिव, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक के लिए करते हैं, मगर चोर वह कहलाते हैं। ऐसा लगता है, कि मानो इन लोगों को खुली छूट दे रखी हो। प्रधान यह कर नहीं बच सकते कि उनका पोषण हो रहा है, जब भी कोई प्रधान खुले आम वीडियो के जरिए शोषण का आवाज उठाता है, तो यही प्रधान लोग है, उसका साथ नहीं देते। यह भी सही है, कि अगर प्रधान चाह जाए तो एक रुपये का घोटाला उसके ग्राम पंचायत में नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जब अधिकांष प्रधान बेईमान हो गए हैं, तो बीडीओ और सचिव कैसे ईमानदार होंगे?

# ....कब मिलेगा ‘लालगंज’ थाने से ‘मालती’ को ‘न्याय’?

## न्याय पाने की आस में लालगंज थाने का चक्कर लगाकर आखें पथरा जा रही, मालती की पीड़ा को देख थाना दिवस दिखावा रह गया

तेजयुग न्यूज

**बस्ती।**...लालगंज थाने के लिए मथौली निवासी मालती देवी पत्नी राम उदित सवाल बनकर पिछले कई थानों से घूम रही हैं। यह पूछती है, कि आखिर उसे कब तक थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा, और कब उसे न्याय मिलेगा? इस सवाल का जबाव षायद थाना दिवस में आने वाले डीएम और एसपी के पास भी नहीं होगा, एसओ साहब की तो बात ही छोड़िए। यह लोग थाना दिवस में आते हैं, आवेदन लेते हैं, निर्देश लिखते हैं, और चायपानी पीकर चले जाते है।

उसके बाद कोई यह नहीं देखता कि उन्होंने जो आदेष और निर्देष दिए थे, उसका पालन हुआ कि नहीं? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? यही कारण है, कि पीड़ितों के लिए थाना दिवस और तहसील दिवस बेमानी साबित हो रहा है। जबकि इन दिवसों को आयोजित करने का मकसद ही सरकार की मंषा पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की है, त्वरित को कौन कहे, अगर किसी को



**❖ हर बार थाना दिवस में महिला को आश्वासन तो मिलता मगर न्याय नहीं मिलता**
**❖ आवेदन पत्र लेकर फरियादी आते, अधिकारी देवते लिखते, फिर चले जाते**



सालभर में न्याय मिल जाए तो बड़ी बात है। जबकि न्याय देने का नियम 28 घंटे के भीतर का है।

नौ मार्च को आयोजित हुआ लालगंज थाना दिवस हवा हवाई साबित हुआ। समाधान दिवस में लगी थानाध्यक्ष एवं राजस्व से संबंधित दोनों कुर्सियां 12.53 बजे तक खाली रही। फरियादी मायूस होकर इधर-उधर टहलते नजर आए, अधिकांश फरियादी निराश होकर घर वापस चले गए, मौखिक में एक पीड़िता मथौली निवासी मालती देवी पत्नी राम उदित ने बताया कि चचेरे ससुर रामसमुझ जिनके कोई संतान नहीं थी। कहा ाकिवह हमारे ही घर पर निवास करते थे। हम लोगों के भरण-पोषण व सेवा सत्कार करने से प्रसन्न होकर अपनी संपूर्ण चल एवं अचल संपत्ति मेरे नाम से रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया। जब तक वह जिंदा थे। तब तक किसी द्वारा कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं किया गया, और न ही किसी विपक्षी ने अपना अधिकार ही जताया। उनकी मृत्यु के बाद हमारे बगल की रहने वाले रामभेज, राम करन, राधेश्याम, राजमन, अवध बिहारी आदि ने मुकदमा दाखिल कर दिया। 2001 से लेकर 2017 तक मुकदमा चला।

17 साल तक मुकदमा चलने के बाद मेरे नाम से डिक्री हुआ। मेरे नाम से दाखिल खारिज भी हो गया। जब मकान गिर गया तो अति गरीबी होने की वजह से निर्माण नहीं करवा पाई। तो उसी स्थान पर पत्थर का पिलर गाड़ कर बांस-बली की सहायता से भरण-पोषण के लिए साग-सब्जी की खेती करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद अज्ञात लोगों द्वारा कुछ माह पहले रात में पिलर उखाड़ कर छोटे-छोटे टुकड़ों में करते हुए लगे बांस-बल्ली को उखाड़ दिया। पूरे साग-सब्जी को नेस्तानाबूद करते हुए मेरे ही बांस बल्ली द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। दूसरे दिन पुनः किसी तरह से बांस-बल्ली की व्यवस्था कर गाड़ने लगी तो उपरोक्त लोगों ने परिवार सहित गाली-गलौज देते हुए मार पीट करने पर अमादा हो गये। गरीबी की वजह से मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है।

तब से लेकर आज तक न्याय पाने के चक्कर में कई समाधान दिवस पर आ चुकी हूं, पुलिस, अधिकारियों से अपनी बात तक कहने नहीं देते। बताया कि आज भी वह थाना दिवस पर अपनी पीड़ा कहने आई मगर कोई साहब ही नहीं मिले। पुलिस मेरे पति व पुत्र को जेल में बंद कर दिया है।

# ‘संजय’ ने अपने नेता ‘पंकज’ का किया जोरदार ‘स्वागत’

तेजयुग न्यूज

**बस्ती :** जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चैधरी ने अपने नेता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का विकास भवन स्थित सरकारी आवास पर जोरदार स्वागत किया। उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेट किया। बता दें कि हाल ही में जिले के प्रथम नागरिक ने मीडिया के सामने मोदी, योगी और पंकज चौधरी है।

शनिवार को देर शाम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बस्ती आगमन पर वह उन्हें अपने सरकारी आवास ले आए और वहां पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया, इस मौके पर सुरेन्द्र त्रिपाठी, सुरेश चौधरी, रजनीश चौधरी, सूरज, महेंद्र उर्फ गुड्डु, आकाश चौधरी, अखिलेश चौधरी विक्की, शिव प्रसाद चौधरी, प्रदीप चौधरी, अनिल पाण्डेय, मनीष राना, आदित्य चौधरी, प्रभात गौतम, अवनीश उर्फ डब्लू, राहुल राजभर, अतुल चौधरी, रमेश चौधरी प्रधान, राहुल पाण्डेय, विकास चौधरी, विश्वनाथ जायसवाल, राजू चौधरी अजय भारती सहित अन्य मौजूद रहे।

# ...जब ‘बच्चे’ ही ‘नहीं’ तो कैसे ‘अनाज’ आता ‘रहा’?

तेजयुग न्यूज

**बस्ती।**...कारनामों के चलते अक्सर मीडिया की सुर्खी बनने वाले बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं, जब इनके अच्छे कार्यो की प्रषंसा हुई होगी। इस विभाग के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार जितना अनियमित कार्यो में लिप्त रहते हैं, उतना अगर नियमित कार्यो में रहते तो विभाग की जय-जयकार के साथ षिक्षा की गुणवत्ता कांवेट स्कूलों जैसी होती। यह विभाग इस बार सरकारी धन की बर्बादी व एमडीएम के राशन को लेकर सुर्खियो में है। बात, कुदरहा ब्लाक के मेहनौना स्थित राम प्रार्षद शास्त्री इंटर कालेज का। यह कालेज जूनियर तक एडेड व माध्यमिक का मान्यता प्राप्त है।

लेकिन यहां न तो माध्यमिक में एक भी बच्चे का नामांकन हुआ है और ही जूनियर में। केवल कागजों में चल रहे इस कालेज के बाबू और अनुचर पर सरकार का प्रतिवर्ष वेतन के रुप में लाखों रुपया बर्वाद हो रहा है। अनुदान व मान्यता बची रहे, इसके लिए प्रबंधन तंत्र ने तो पहले फर्जी नामांकन कर विद्यालय को गुलजार करने की भरपूर कोशिश की। एक दो वर्ष तक चलाया भी। लेकिन नामांकित बच्चों का विवरण पोर्टल पर अपलोड़ की व्यवस्था के आगे प्रबंधन तंत्र का फर्जीवाड़ा फेल हो गया और बच्चों की संख्या कालेज में शून्य हो गई। अब सवाल खड़ा होता है जब तीन वर्ष से कालेज में शिक्षक नहीं है। छात्र संख्या भी शून्य है, तो बाबू व अनुचर वहां कर क्या रहे हैं? क्यों कि इन परन वेतन के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। अगर इन्हे किसी विभागीय कार्यालय व स्कूलों में अटैच कर दिया जाता तो कम से कम धन की बर्बादी न होती और वहां के स्टाफ को काफी साहूलिय भी मिलती। लेकिन विभाग के जिम्मेदारों को इससे क्या लेना देना। घर से थोड़े देना है, सरकार



**❖ बिना शिक्षक और बच्चों के बाबू व अनुचर पर विभाग लुटाता रहा धन**

का माल है, बर्वाद होने दो।

कालेज में फर्जी नामांकन के चलते राशन का उपभोग भी उतना ही हुआ जितना हकीकत में बच्चे थे। लेकिन विभाग नामांकन के सापेक्ष राशन ठेलता गया। कभी उपभोग प्रमाण पत्र पर ध्यान देने की जरुरत ही नहीं समझी। जबकि कालेज के द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर राशन का उपभोग व अवशेष अपलोड़ किया जाता रहा।

कोरोना काल में जब 24 क्विंटल राशन कोटेदार के पास डंप हो गया और विद्यालय के खाते मे करीब 70 हजार रुपये कन्वर्ज कास्ट का। दो वर्ष तक विभागीय जिम्मेदार को इसकी जानकारी ही नहीं हुई। बल्कि दिसंबर 2022 तक राशन आना जारी रहा। गोदाम में राशन खराब होने व कालेज द्वारा उठाना न किए जाने की जानकारी जब कोटेदार ने एमडीएम जिला समन्वयक को दी तो उन्होने राशन भेजना बंद कर दिया ।लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जब कालेज में बच्चे ही नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में राशन की खतप कैसे होगी ।डेढ़ वर्ष बाद जब मामला चर्चा में फिर आया तो विभाग की नीद खुला। शायद कोटेदार ने सूचित न किया होता तो विभाग राशन ठेलता ही रहता और आज बिन बच्चों के कालेज का पचासो क्विंटल से अधिक डंप होकर सड़ता ।

# ...जब ‘लाखों’ में मिलती ‘प्रधानी’, तो ‘क्यों’ न करें ‘घोटाला’?

## मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी/बीडीओ के चलते ग्राम पंचायतों में फैला भ्रष्टाचार, बखरा ने प्रधानों के साथ बीडीओ को भी चोरों वाली श्रेणी में खड़ा कर दिया

तेजयुग न्यूज

**बस्ती।**....अधिकांश प्रधानों का कहना है, कि जब उन्हें लाखों में प्रधानी मिली है, तो वह क्यों ने मनरेगा को लूटे। देखा जाए तो विकासखंड रुधौली में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही इस ब्लॉक में कोई नया बीडीओ आता है, सबसे पहले वह बखरा की बात करता है। अधिकांष बीडीओ तो इस लिए एडवांस में पूरा का पूरा यानि सात फीसद बखरा इस लिए प्रधान से ले लेतें हैं, कि पता नहीं कब उनका तबादला हो जाए। इसके पूर्व जो भी खंड विकास अधिकारी आए, उन्होंने टीएस के नाम पर एक फीसद, स्वीकृति के नाम पर चार प्रतिशत और भुगतान के नाम पर तीन फीसद बखरा लेते है।

लेकिन वर्तमान के खंड विकास अधिकारी अपना स्थानांतरण के डर से पहले ही बखरा लेने के लिए उग्र हो गए हैं। आपको बताते चलें विकास खंड रुधौली की कई ग्राम पंचायत के प्रधानों ने अपनी ग्राम प्रधानी छोड़ने की बात कही है, इसके पूर्व में बाघाडीहा के प्रधान रजनीश सिंह का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कमीशन पहले दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रुधौली विकासखंड में हो रहे

**❖ यह सबकुछ करने को तैयार है, मगर बखरा नहीं छोड़ सकते**

भ्रष्टाचार को लेकर उच्च अधिकारियों के कान के नीचे जूं तक जा रहा है। जांच के नाम पर खुद अधिकारी भी आकर अपना बखरा लेकर गलत को सही साबित कर देते हैं।

विकासखंड रुधौली के एक ग्राम प्रधान ने (नाम न छापने की शर्त पर बताया कि) यदि आपको जमीन पर कार्य देखना है तो सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर लेने वाले 28 प्रतिशत कमीशन को बंद कराया जाए। उसके बाद हर ग्राम प्रधान अपना कार्य ईमानदारी तरीके से कराएगा। आपको बताते चलें इसके पूर्व में खंड विकास अधिकारी धनेश यादव पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहें। वही आरोप नए खंड विकास अधिकारी विनय कुमार द्विवेदी पर भी लगने लगा। विकासखंड रुधौली के ग्राम पंचायत तिगोडिया में सात मार्च 2024 को खुर्शीद अली के चक से मेन सड़क तक घोला खुदाई कार्य के नाम पर चार मास्टर रोल में कुल 39 मजदूरों की फर्जी हाजीरी लगाई गई जमीनी स्तर पर जब मीडिया टीम में पड़ताल किया तो वहां पर एक भी मजदूर न मिलने से ग्राम प्रधान व भ्रष्ट सचिव उमेश कुमार के हाथ पांव फूल गए।

जब इस प्रकरण में ग्राम प्रधान अब्दुल रज्जाक खान से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में एक युवक की मौत हो गई है, जिसकी वजह से मजदूर उनको मिट्टी देने गए हैं। जब इस प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी उमेश कुमार से वार्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मिलकर बात करें। सारी बात फोन पर नही की जा सकती।